Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. VI, Issue No. XII, October-2013, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

उपनिवेशवाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ई-कॉमर्स तक

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. VI, Issue No. XII, October-2013, ISSN 2230-7540

उपनिवेशवाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ई-कॉमर्स तक

Anita Pandey*

Research Scholar, Mahatama Gandhi Kashi Vidya Peeth University, Varanasi (UP)

---------------------------------- x ----------------------------------

ईस्ट इंडिया कंपनी

ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूरे देश पर शासन करने का असामान्य भेद था। इसकी उत्पत्ति बहुत हदबंदी थी 31 दिसंबर 1600 को, ईस्ट इंडिया कंपनी में खुद को शामिल करने वाले व्यापारियों का एक समूह ईस्ट इंडीज के साथ सभी व्यापार पर एकाधिकार विशेषाधिकार दिया गया। कंपनी के जहाज पहले भारत में, सूरत में बंदरगाह पर 1608 में पहुंचे थे। सर थॉमस रो 16 वीं में राजा जेम्स आई के दूत के रूप में मुग़ल सम्राट, जहांगीर की अदालत में पहुंचे और अंग्रेजों के लिए एक स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया सूरत में कारखाना धीरे-धीरे ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों को ग्रहण कर दिया और पिछले कुछ सालों में उन्होंने भारत में अपने व्यापारिक परिचालनों का भारी विस्तार देखा। भारत के पूर्व और पश्चिम किनारों पर कई व्यापारिक पद स्थापित किए गए थे, और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के तीन राष्ट्रपति कस्बों के आसपास काफी अंग्रेजी समुदाय विकसित हुए थे। 1717 में, कंपनी ने अपनी सबसे उल्लेखनीय सफलता हासिल की जब बंगाल में कस्टम ड्यूटी के भुगतान से कंपनी को मुगल सम्राट से छूटने वाले एक फ़िरमन या शाही तानाशाह प्राप्त हुआ।

भारत में उस समय इंटीग्रल मानवतावाद

कंपनी ने अपनी किस्मत का उदय, और एक व्यापारिक उद्यम से एक सत्तारूढ़ उद्यम में परिवर्तन देखा, जब उसके एक सैन्य अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराज-उद-दुलह की सेना को पराजित किया 1757 में प्लासी। कुछ साल बाद कंपनी ने मुगल सम्राट की ओर से राजस्व एकत्र करने का अधिकार हासिल कर लिया, लेकिन इसके प्रशासन के शुरुआती वर्षों बंगाल के लोगों के लिए दुःख थे। कंपनी के दास बड़े पैमाने पर एक रूढ़िवादी और आत्म-उन्नयन के थे, और बंगाल की लूट ने पूर्व में अमीर प्रांत छोड़ दिया था, जो एक निराशाजनक स्थिति में थे। 1769-70 की अकाल, जिसकी कंपनी की नीतियों को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया, शायद आबादी के एक तिहाई के रूप में जीवन ले लिया हो। व्यापार में बढ़ोतरी और अन्य स्रोतों से आने वाले राजस्व के बावजूद कंपनी ने खुद को भारी सैन्य व्यय के साथ बोझ किया, और इसका विनाश आसन्न हो गया। राज्य के हस्तक्षेप ने बीमार कंपनी को अपने पैरों पर रख दिया और भगवान उत्तर के भारत विधेयक को 1773 के विनियमन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, जो कि कंपनी के मामलों पर अधिक से अधिक संसदीय नियंत्रण प्रदान करता है, भारत को एक गवर्नर-जनरल के शासन के अधीन रखने के अलावा।

भारत के पहले गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे अपने आचरण के तहत, भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार सख्ती से किया गया, और अंग्रेजों ने ज्ञान की स्वदेशी प्रणाली को मास्टर करने की मांग की। हेस्टिंग्स 1784 तक भारत में बने रहे और कॉर्नवॉलिस द्वारा सफल हुए, जिन्होंने स्थायी सेटलमेंट की शुरुआत की, जिसके तहत राजस्व संग्रह के लिए ज़मीनदारों या जमींदारों के साथ एक समझौता किया गया। अगले पचास वर्षों तक, ब्रिटिश भारतीय प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के प्रयासों में लगे हुए थे, और यह वेलेसली के प्रशासन के अधीन है कि ब्रिटिश क्षेत्रीय विस्तार क्रूर दक्षता से प्राप्त किया गया था। मैसूर और मैराथन के टीपू सुल्तान के खिलाफ मेजर जीत हासिल हुई थी और आखिर में एंग्लो-सिख युद्धों की एक श्रृंखला में अधीनता और सिखों पर विजय पूरी तरह से भारत के ब्रिटिश कब्जे में आया। कुछ जगहों पर, ब्रिटिश ने अप्रत्यक्ष शासन किया, देशी शासकों की अदालत में निवास करने वाले को घरेलू मामलों में संप्रभुता की अनुमति दी गई थी। लॉर्ड डलहौज़ी की कुख्यात सिद्धांत, जिसके तहत एक देशी राज्य ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया, अगर शासक की मौत पर कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, तो

वह मूल साधनों में से एक था, जिसके द्वारा देशी राज्यों को एकजुट किया गया; लेकिन अक्सर 1856 में अवध [औध] जैसे एकीकरण, इस आधार पर न्यायसंगत था कि मूल राजकुमार बुरा स्वभाव से था, अपने विषयों के कल्याण के प्रति उदासीन। देशी राज्यों, कठोर राजस्व नीतियों और भारतीय किसानों की दुर्दशा ने 1857-58 के विद्रोह में योगदान दिया था, जिसे पहले सिपाही विद्रोह के रूप में संदर्भित किया गया था। 1858 में जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा अपनी कथित उपलब्धियों की रक्षा के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, और भारत का प्रशासन क्राउन की जिम्मेदारी बन गया।

दीनदयाल उपाध्याय का अभिन्न मानववाद जनसंघ की सिद्धांतों और नीतियां

सिद्धांतों और नीतियां

लोकतांत्रिकता, समानता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और विश्व शांति अंतःसंबंधित अवधारणाओं लेकिन पश्चिम में इन अवधारणाओं को अक्सर एक-दूसरे के साथ झगड़ा होता है। इस संघर्ष का समाधान करने के प्रयासों से समाजवाद और एक-विश्व सरकार के विचारों ने प्रयास किए हैं। हालांकि, वे केवल ऐसा करने में असफल नहीं हुए हैं लेकिन इन अवधारणाओं को कमजोर कर दिया है और नई समस्याएं बनाई हैं। भारतीय संस्कृति के आधार पर दार्शनिक बुनियाद प्रदान करता है जिसके आधार पर इन अवधारणाओं को सुसंगत और पोषित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तरह के आधार की अनुपस्थिति में, मानव विचार और विकास को हताश किया गया है। भारतीय संस्कृति द्वारा प्रस्तावित मूलभूत सत्यों को देश और उम्र से परे एक वैधता है। इसलिए, इन सच्चाइयों का ज्ञान न केवल हमारी अपनी उन्नति के लिए, बल्कि दुनिया की प्रगति के लिए ही दिशा प्रदान करेगा।

भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण अभिन्न है। यह विभिन्न संस्थाओं और जीवन के पहलुओं के बीच असंतुलित मतभेदों को स्वीकार करता है, लेकिन यह एक ही समय में उन्हें अंतर्निहित एकता को खोजना चाहता है- और पूरे दृश्य के एक एकीकृत दृष्टिकोण को लेता है, दुनिया की कई गुंजाइशों में, भारतीय संस्कृति अंतर- विरोध, विरोधाभास और विवाद के बजाय सहयोग, समन्वय और सहयोग। इसका परिप्रेक्ष्य सभी व्यापक है, आंशिक नहीं है। यह शुभकामनाएं और काम करता है। इंटीग्रलिज़्म इस प्रकार इसकी महत्वपूर्ण-नोट है

व्यक्तिगत और सोसायटी

पश्चिम के कई विचारधारा इस धारणा पर आधारित हैं कि व्यक्तिगत और समाज के बीच अंतर्निहित संघर्ष है। ये विचारधारा तब एक या दूसरे के कारण का कारण उठाते हैं लेकिन तथ्य यह है कि दोनों संस्थाओं के बीच ऐसा कोई अंतर्निहित संघर्ष नहीं है। दिखाई देने वाली संस्था-अविभाज्य-अदृश्य समाज का प्रतिनिधि भी है। यह उनके माध्यम से है कि समाज स्वयं प्रकट होता है। वह वास्तव में समाज का मुख्य साधन है, और इसकी पूर्ति के उपाय अपने व्यक्तित्व का विनाश या कसना समाज छोड़कर छोड़ देगा। एक फूल इसकी पंखुड़ियों के कारण होता है, और पंखुड़ियों के मूल्य फूल के साथ शेष रहते हैं और इसकी सुंदरता को जोड़ना व्यक्तिगत और सामाजिक अच्छे का विकास विरोधाभासी रूचि नहीं है।

व्यक्तिगत की ऑल-राउंड प्रगति

एक व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का कुल योग है ! व्यक्ति के सभी दौर की प्रगति के इच्छुक व्यक्ति को उसके सभी गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। उन सभी को संतुष्ट होना चाहिए। तभी एक व्यक्ति को वास्तविक खुशी का अनुभव होगा इसका मतलब यह है कि दोनों सामग्री, साथ ही आध्यात्मिक, प्रगति के उद्देश्य से किया जाना चाहिए इन चार गुना इच्छाओं को दूर करने के लिए साधन भौतिक अर्थ, शांति, ज्ञान और तात्तममा (पहचान) की भावना है। यह इस उद्देश्य की व्यापक प्रकृति है जो व्यक्ति को सामाजिक अच्छे के लिए उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है।

व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक कल्याण के इस जुड़वां उद्देश्य की उपलब्धि के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चार पुरूषों को इस रूप में प्राप्त किया गया है। धर्म, अर्थ और काम, एक दूसरे को बनाए रखते हैं और पूरक हैं। मानव गतिविधि के एकमात्र प्रेरक के रूप में उनमें से किसी एक को स्वीकार करने के लिए और अकेले ही उपाय के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए, चीजों के बारे में एक तरह का दृष्टिकोण रखना होगा। हालांकि, धर्म, अर्थ और काम का एहसास करने का साधन, मुख्य महत्व का है

धर्म की प्रकृति

धर्म या पंथ के साथ धर्म का योग करने के लिए बहुत भ्रम है। धर्म का मतलब वास्तव में उन अनन्त सिद्धांतों का मतलब है जो किसी संस्था को बनाए रखे हैं - व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट-और जिसके द्वारा पालन किया जा रहा है, वह इकाई इस दुनिया में भौतिक समृद्धि और अगले में

आध्यात्मिक उद्धार प्राप्त कर सकती है। धर्म की बुनियादी विशेषताएं अनन्त और अपरिवर्तनीय हैं। लेकिन इन सिद्धांतों से विस्तृत स्पेलिंग के मामले में, धर्मादास स्थान और अवधि के अनुसार अलग-अलग होते हैं। फिर भी इस विश्व में परिवर्तन, धर्म ही एकमात्र कारक है जो समाज के लिए स्थिरता लाता है। इसलिए भारतीय राजनीति के अनुसार, पूर्ण संप्रभुता अकेले धर्म में निहित है।

समाज केवल व्यक्तियों का एक समूह नहीं है यह अपने आप में एक जीवित संस्था है एक ऐसा समाज जिसने अपने देश के लिए भव्य भक्ति और एक विशिष्ट प्रतिभाशाली, एक राष्ट्र का गठन किया है। प्रतिभा सहज और जन्मजात है और न केवल भूगोल और इतिहास के उत्पाद। राष्ट्रों का उदय और गिरावट बहुत ही इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी आचरण अपनी प्रतिभा के अनुरूप कितनी दूर है लेकिन उनकी विविधताओं के बावजूद, विभिन्न राष्ट्र दुनिया की एकता के निर्माण में एक पूरक भूमिका निभा सकते हैं। यदि किसी भी देश ऐसा नहीं करता है और एकता को खराब करता है, तो इसे एक विकृति माना जाना चाहिए। विश्व की एकता का निर्माण करने के लिए राष्ट्रों के साथ दूर करने की कोशिश करना होगा कि वह कॉर्पोरेट व्यथा को बढ़ावा देने के नाम पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को ध्वस्त करने जैसा होगा।

इंस्टीट्यूशंस के उत्पत्ति

अपने आप को प्रकट करने के लिए, और इन चार पुरूषों को व्यक्तिगत अभ्यास में मदद करने के लिए, समाज कई तरह के संस्थानों को जन्म देती है जैसे कि विवाह, परिवार, संपत्ति, जाति, कबीले, समुदाय, समाज, पंचायत, राज्य आदि। राज्य महत्वपूर्ण है ¬tant, लेकिन सर्वोच्च नहीं

कृता-युग में, वे कहते हैं, सभी पुरुषों को धर्म द्वारा एक दूसरे के प्रति उनके व्यवहार में निर्देशित किया गया था, इसलिए कोई राज्य नहीं था यह समाज की आदर्शवादी की हमारी अवधारणा है- राज्यविहीन, और धर्म द्वारा पूरी तरह से विनियमित। यह तभी संभव है जब हर कोई निर्मल और धर्म-निष्ठा बन जाए। लेकिन आम तौर पर, व्यवस्था की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने के लिए सभी अवसरों का आश्वासन देना होगा।

धर्म राज्य-हमारा आदर्श

भारतीय राज्य का आदर्श धर्म राज्य रहा है सभी धर्मों और creeds के लिए सहिष्णुता और सम्मान भारतीय राज्य की एक अनिवार्य विशेषता है। पूजा और विवेक की स्वतंत्रता सभी के लिए गारंटी है और राज्य किसी भी धर्म के आधार पर या नीति के निर्माण में उसके कार्यान्वयन में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। यह एक गैर-सांप्रदायिक राज्य है और एक थियोक्रिक नहीं है

धर्म राज्य किसी भी व्यक्ति या शरीर को प्रभु के रूप में नहीं पहचानता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ दायित्वों और नियमों के अधीन है कार्यपालिका के अधिकारियों, साथ ही लोगों के अधिकार, धर्म द्वारा निर्धारित और विनियमित होते हैं। विशिष्ट आचरण की अनुमति नहीं है। धर्म राज्य राज्य कानून के निकटतम अंग्रेजी समकक्ष धर्म राज्य एक तरफ मध्यस्थता और अधिनायकवाद पर रोक देता है, और दूसरी ओर यह लोकतंत्र को मोक्षपरायण में घटने से रोकता है। जबकि राज्य की अन्य अवधारणाएं सही दिशा में हैं, धर्म राज्य की भारतीय अवधारणा कर्तव्य उन्मुख है। इसलिए स्वाभाविक रूप से, असीमित अधिकारों के बाद अधिकारों को कुचलने के लिए या किसी भी चीज के लिए यहां कोई मौका नहीं है। इसके अलावा, कर्तव्य की कमी, पावर-पागलपन या अधिकारों के किसी भी संघर्ष का कोई खतरा नहीं है।

कर्तव्यों और अधिकार

एक धर्म राज्य में लोगों के अधिकार अनन्य हैं। यह लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने अधिकारों के इन अधिकारों की रक्षा करें क्योंकि ये इन अधिकारों के प्रयोग से है कि वे अपनी धर्म को पूरा कर सकते हैं। वास्तव में, हमारी अवधारणा के अनुसार, एक अधिकार एक साधन है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और अनुभवों को समझने के लिए सक्षम बनाता है, और संबंधित है। ड्यूटी और सही इस प्रकार त्रिकोण के दो पक्ष हैं जिनके पास धर्म है क्योंकि यह आधार है। यह हथियारों से सुसज्जित एक सैनिक का अधिकार है, क्योंकि हथियारों के बिना वह लोगों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इन हथियारों को कैसे प्रदान किया जाना है, और इसका प्रयोग किया जाता है, यह पूरी तरह धर्म से संचालित होता है।

जनतंत्र

लोकतंत्र, या लोक नियम (लोक-तंत्र) लोकाधारी (लोगों के अधिकार) को कायम रखने और लोक-कर्ता (लोगों का कर्तव्य) को बढ़ावा देने का एक साधन है। लोकतंत्र को न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाना है। वास्तव में लोकतंत्र अविभाज्य है यह टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता है किसी भी एक क्षेत्र में लोकतंत्र की अनुपस्थिति बाकी पर बाकी लोकतंत्र के विकास को प्रभावित करती है। सहिष्णुता, व्यक्ति की गरिमा और जन-अभिव्यक्ति के साथ पहचान-भावना की भावना, लोगों-ये लोकतंत्र की आवश्यक हैं। इनके बिना, लोकतंत्र का मात्र सामान बेकार होगा। और अगर ये आवश्यक हैं, तो संस्थागत रूप समय-समय पर और देश-देश में भिन्न हो सकते हैं।

राजनीतिक लोकतंत्र की मुख्य विशेषता प्रतिनिधि शासकों का चयन करने और इस तरह से निर्वाचित होने का अधिकार है। आर्थिक लोकतंत्र के लिए व्यवसाय और स्वतंत्रता की स्वतंत्रता जरूरी है। और सामाजिक लोकतंत्र स्थिति और अवसर की समानता से उत्पन्न होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि ये सभी अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और दूसरों के प्रभाव से नहीं हटते हैं

आजादी

व्यक्तियों के लिए और साथ ही राष्ट्रों के लिए, स्वतंत्रता एक प्राकृतिक आग्रह है बंधन में न तो खुशी है और न ही शांति है राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक मुक्ति भी आवश्यक है राज्य द्वारा व्यक्ति और समाज के प्राकृतिक हितों में गैर हस्तक्षेप राजनीतिक स्वतंत्रता का गठन करता है आर्थिक स्वतंत्रता अर्थ में है कि मनुष्य की प्रगति के लिए सकारात्मक या नकारात्मक बाधा का कोई मतलब नहीं है। अंततः एक ऐसी स्थिति जिसमें सोसाइटी व्यक्ति की प्राकृतिक प्रगति में योगदान देती है, इसे प्रतिबंधित करने की बजाय सामाजिक आजादी है। ये स्वतंत्रता केवल उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जब राष्ट्र उन्हें आनंद लेती है।

लोकतंत्र की तरह, स्वतंत्रता भी अविभाजित है। राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना, अन्य दो स्वतंत्रताएं होना असंभव है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना, लोगों को सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, और बहुत हद तक राजनीतिक स्वतंत्रता भी हो सकती है। और सामाजिक स्वतंत्रता के साथ, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी पदार्थ खो देंगे।

अर्थव्यवस्था का विनियमन

राजनीति के दायरे में, आर्थिक मामलों में, लाइसस .: न्याय केवल कविता-युग के अंतर्गत आता है। इसमें केवल एक आदर्श राज्य में प्रासंगिकता हो सकती है। अतः, उचित उत्पादन, वितरण और धन की खपत, अर्थव्यवस्था का नियमन (अर्थयामा) सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है इस प्रयोजन के लिए विभिन्न संस्थानों ने आकार ले लिया है। राज्य में भी भारी जिम्मेदारी इस संबंध में है।

लेकिन राज्य में स्वामित्व और उत्पादन के सभी साधनों का नियंत्रण करने के लिए आर्थिक और साथ ही राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण को जन्म देगा। यह गलत होगा हालांकि, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए, अर्थव्यवस्था को किसी भी उलझन में रखने के लिए और राष्ट्र के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य को सामान्यतः योजना, प्रत्यक्ष, विनियमन और नियंत्रण के लिए कार्य करना चाहिए। आर्थिक प्रयास और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों और परिस्थितियों में भी स्वामित्व और प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए।

अर्थ और समृद्धि चाहते हैं

अर्थ की इच्छा के लिए, धर्म ग्रस्त है। इसके समृद्ध होने से धर्म भी भुगत सकता है। दोनों परिस्थितियों में, आर्थिक स्वतंत्रता कटौती की जाती है। पर्याप्त आजीविका या उत्पादन को बनाए रखने या इसे बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी की कमी की उपलब्धता नहीं है, अर्थ की आवश्यकता नहीं है। यह व्यक्तिगत और साथ ही समाज दोनों पर लागू होता है। धन को सम्बन्ध रखने का यह तथ्य भूल गया है कि धन ही एक साधन है, एक धर्म-विनियमित इच्छा, ज्ञान और धन का आनंद, धन और धन के अनुचित प्रभाव, समाज में आर्थिक असमानता, मुद्रास्फीति और देवूलुआ-सबके सबूत हैं। ऐसी स्थितियां जो एक अर्थ-जटिल धर्म के लिए हानिकारक हैं। ऐसे अतिरिक्त मनुष्य की ऊर्जा को कम कर देता है और अंततः धन और समृद्धि का अपव्यय होता है।

संपत्ति का स्वामित्व

संपत्ति के स्वामित्व का मुद्दा महत्वपूर्ण है कुछ लोग यह मानते हैं कि संपत्ति का एक अविभाज्य अधिकार पूर्ण है। ऐसे अन्य लोग हैं जो संपत्ति के स्वामित्व और विशेष रूप

www.ignited.in

से उत्पादन के साधनों पर विचार करते हैं, क्योंकि सभी बुराइयों के मूल कारण हैं। ऐसे विचारक हैं जो इस विचार की सब्सक्राइब करते हैं कि सभी संपत्ति भगवान और पुरुष के हैं लेकिन वही ट्रस्टी हैं। एक दर्शन के रूप में, ट्रस्टीशिप की यह अवधारणा सुगम है लेकिन वास्तविक प्रथा में, प्रश्न हमेशा वही रहेंगे जो नतीजे और सीमाओं को ट्रस्टी के आचरण का मार्गदर्शन करना चाहिए।

एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह, जिसके साथ व्यक्ति अपनी सभी जरूरतों और गतिविधियों के बारे में असुरक्षित संबंधित है, बिना संपत्ति के रह सकते हैं। कर्मा (कार्यवाही) के साथ फल उसके साथ जुड़ा हुआ है स्वतंत्रता से उपभोग करने और उसका उपयोग करने के लिए जो एक अर्जित किया है, वह संपत्ति की अवधारणा उपजा है। संपूर्ण आय का उपभोग नहीं करने के लिए, लेकिन वहां से बचाने के लिए एक प्राकृतिक प्रवृत्ति और एक राष्ट्रीय गुण है। संपत्ति व्यक्ति को गरिमा, सुरक्षा और संतुष्टि की भावना देती है। इसलिए संपत्ति को दूर नहीं किया जा सकता।

संपत्ति का अधिकार सामाजिक स्वीकृति के अधीन है। प्रॉपर्टी के बारे में यह अवधारणा एक काफी जटिल है और समय, स्थान और वस्तु के साथ भिन्न होता है। समाज की अलग-अलग जरूरतों के साथ मतभेद उत्पन्न होते हैं। जो लोग संपत्ति का नियमन करने का अधिकार समाज से वंचित करते हैं, वे चाहते हैं कि किसी विशेष क्षण में प्रचलित संपत्ति के बारे में अवधारणाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। सोसाइटी का अधिकार है, और संपत्ति के अधिकारों को बदलने के लिए अक्सर यह अपना कर्तव्य बन जाता है संपत्ति का एक पूर्ण और निर्बाध अधिकार जैसी कोई चीज नहीं है

संपत्ति का अधिकार हालांकि सीमाओं के अधीन मान्यता प्राप्त करना होगा। ये सीमाएं समाज की आवश्यकताओं और जीवन-मूल्यों और व्यक्ति के अनुसार निर्धारित होती हैं। जब संपत्ति की समृद्धि कुछ व्यक्ति सुस्त या परजीवी बनाता है और इसकी कमी दूसरों को अपनी आजादी से वंचित करती है, तो यह संपत्ति को विनियमित करने के लिए जरूरी हो जाता है

मुख्य रूप से, यह संपत्ति की प्रचलित अवधारणाओं में परिवर्तन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रदान करने के लिए समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन मुआवजे के प्रिंसिपल अनिवार्यता और स्थिरता को देखते हुए जरूरी है जो इसे प्रदान करता है।

एक ध्वनि आर्थिक प्रणाली का टचस्टोन

किसी देश की आर्थिक व्यवस्था के रूप में, अपनी राजनीति के रूप में, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास होना चाहिए। धन का उत्पादन मुख्य रूप से मनुष्य को खुशी देने के लिए करना है। मानव श्रम उत्पादन का प्राथमिक साधन है मनुष्य की आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाना है। इसलिए, यह व्यवस्था सबसे अच्छी है जो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सहायता करती है और साथ ही अपने आधिकारिक कल्याण को भी बढ़ावा देती है। एक प्रणाली जो अपने आर्थिक अच्छे होने की प्रगति करती है लेकिन अन्य दिशाओं में अपनी प्रगति को बाधित करती है, उसे लाभकारी नहीं माना जा सकता है। हर आर्थिक प्रणाली के लिए ब्याज का केंद्र बिन्दु मनुष्य होना चाहिए।

अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी व्यवस्था जो 'आर्थिक व्यक्ति' को अपनी गतिविधियों के केंद्रीय बिंदु के रूप में स्वीकार करती है, वह अपर्याप्त है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की स्वार्थी इच्छा इस प्रणाली में प्रेरक शक्ति है, प्रतियोगिता के साथ-साथ अपने नियामक के रूप में। यह भारतीय दर्शन के अनुरूप नहीं है पूंजीवाद द्वारा बनाई गई समस्याओं की प्रतिक्रिया में सोशलिस्टवाद उत्पन्न हुआ इसका उद्देश्य प्रशंसनीय है, लेकिन इसके अंत में, यह मानव जाति के लाभ में विफल रहा है। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक समाजवाद के प्रहार करने वाले कार्ल मार्क्स द्वारा समाज और व्यक्ति का विश्लेषण मूल रूप से भौतिकवादी है और इतना अपर्याप्त है। वर्ग-संघर्ष की अवधारणा सहज और स्थायी सहयोग की भावना को जन्म नहीं दे सकती है।

पूंजीवाद और समाजवाद संपत्ति के उनके दृष्टिकोण में भिन्नता है। लेकिन दोनों अपने केंद्रीकरण और एकाधिकार के लिए सीसा। तो मनुष्य को दोनों के बीच उपेक्षित किया जाता है हमें एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जिसमें मनुष्य की अपनी पहल बेजोड़ होती है लेकिन जिसमें बाकी समाज के साथ उसके संबंध में, मानव मूल्यों को प्रभावित नहीं होता है। यह उद्देश्य अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था

सत्ता का एकाग्रता लोकतंत्र और मानव स्वतंत्रता के प्रति प्रतिकूल है। राष्ट्रीय एकता के बारे में विचार करने के विषय में, आर्थिक शक्ति को क्षैतिज और लंबवत रूप से दोनों विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए। पश्चिम में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने शक्ति की एकाग्रता को जन्म दिया है। सार्वजनिक लिमिट कंपनी, प्रबंध एजेंसी, होल्डिंग कंपनी आदि के संस्थानों ने कुछ हाथों में धन और शक्ति के संचय को आगे बढ़ाया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अधिकांश बुराइयों को केंद्रीकरण के लिए देना है। इस केंद्रीकरण में सोशलिस्ट प्रणाली ने कोई बुराई नहीं देखी उन्होंने केवल निजी हाथों से राज्य के स्वामित्व को हस्तांतरित करने की मांग की वास्तव में एक समाजवादी शासन के तहत दोनों आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां एक ही हाथ में केंद्रित हैं, और इसलिए, एकाग्रता के कारण बुराइयों को और भी अधिक बल दिया जाता है। इन बीमारियों को केवल विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। तदनुसार सामाजिक और आर्थिक संस्थानों को मान्यता दी जानी होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवीनतम आविष्कार विकेन्द्रीकृत उद्योगों का समर्थन करते हैं। विकेंद्रीकरण मानवीय व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद अनुकूल है। छोटे पैमाने पर मैकेनाइज्ड उद्योग, छोटे व्यापार और खेतों जो व्यक्तिगत, पारिवारिक या सहकारी स्वामित्व के तहत चलने और प्रबंधित किए जा सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार होना चाहिए। बड़ी इकाइयों को इस नियम के अपवाद होना चाहिए।

प्रगति का मानदंड

यह समाज की ज़िम्मेदारी है कि वह प्रत्येक बच्चे के रखरखाव की व्यवस्था करे, और उन्हें शिक्षा प्रदान करे जिससे वह अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकें, जैसे कि वह एक जिम्मेदार स्मृति के रूप में समाज की भलाई में योगदान देता है। यह समाज की जिम्मेदारी है कि हर सक्षम शरीर को रोजगार और पर्याप्त अवकाश और हर व्यक्ति को जीवित रहने का आश्वासन दिया जाए। हर सभ्य समाज किसी भी रूप या अन्य में इन दायित्वों को पूरा करता है। वास्तव में, ये प्रगति का मुख्य मानदंड बन गए हैं। इसलिए, न्यूनतम रहने वाले मानक, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाना होगा।

इंटीग्रल मानवतावाद

व्यक्ति हमारी प्रणाली में एक निर्णायक स्थिति में रहती है, 'यित पिंडे तड़ ब्रह्मांद' (जो कि सूक्ष्म जगत में भी है) के सिद्धांत के अनुसार, व्यक्तिगत प्रतिनिधि और समाज का मुख्य साधन है। भौतिक धन मनुष्य की खुशी के लिए एक साधन है, और अपने आप में अंत नहीं है लेकिन एक ऐसी प्रणाली जो जन-जन की धारणा के आधार पर आती है और यह ध्यान में नहीं ले पाती कि जीवित व्यक्ति का व्यक्तित्व विशिष्टतापूर्ण रूप से खुद ही पर्याप्त नहीं है अपर्याप्त भी एक ऐसी प्रणाली है जो मनुष्य के एक विशेषता पर दिखता है और उसके बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण लेने में विफल रहता है जैसे कि शेयरधारक, मन, बुद्ध और आत्मा का एक जैविक अस्तित्व है जिसमें पुरूषार्थों द्वारा पूरा करने की आवश्यकता वाले बहुत से आग्रह हैं। हमारा आदर्श अभिन्न व्यक्ति है, जिसमें एक साथ अनगिनत व्यक्ति और कॉर्पोरेट संस्थाओं को साझा करने की क्षमता है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कोने का पत्थर है जिस पर हमारी पूरी प्रणाली का निर्माण करना आवश्यक है।

कई स्कूलों ने किया है जिन्होंने मानवतावाद को बढ़ाया है लेकिन पश्चिमी विचारधाराओं में उनकी सोच निहित है और इसलिए यह अनिवार्य रूप से भौतिकवादी है। ये विचारक मनुष्य के नैतिक प्रकृति या व्यवहार के लिए कोई दार्शनिक व्याख्या नहीं दे पाए हैं। अगर आप अध्यात्मवाद से इंकार करते हैं, तो मानव रिलायंस और व्यवहार और मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच संबंधों को समझाया नहीं जा सकता है।

अपिंग पश्चिमी विचारधारा

भारत में अधिकांश राजनीतिक दल पश्चिमी विचारधारा से प्रेरित हैं। वे पश्चिम के एक या अन्य राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ हैं और वहां इसी संस्थान के प्रतिकृति हैं। वे भारत की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते और न ही क्रॉस-सड़कों पर खड़े विश्व के किसी भी मार्गदर्शन के लिए वे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण करती हैं, वे भाराईया संस्कृति की गतिशीलता को याद करते हैं, और भारतीय मूल्यों की शाश्वत और स्थायी प्रकृति उन्हें एक स्थिर और अनम्य चरित्र के प्रमाण के रूप में प्रकट होती है। इसलिए, वे जघन्य निर्देशों और पिछले युग की प्रथाओं की रक्षा करने की कोशिश करते हैं और यथास्थिति के लिए अनुरोध करते हैं। वे भारतीय संस्कृति में क्रांतिकारी तत्व का अनुभव करने में नाकाम रहे

हैं। वास्तव में समाज में प्रचलित कई अप्रियताएं, जैसे कि अछूतता, जाति भेदभाव, दहेज, मौत के उत्सव, महिलाओं की उपेक्षा आदि। खराब स्वास्थ्य और अध: पतन के लक्षण हैं। भारत के कई महान पुरुष भारतीय संस कृतियों के प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने पिछले कुछ समय से इन बुराइयों से संघर्ष किया है। हमारे बहुत से सामाजिक और ईकोणोमी व्यवस्थाओं का एक विश्लेषण यह प्रकट करेगा कि वे या तो समय के साथ बदलने और समायोजित करने के लिए समाज की अक्षमता का नतीजा है, या वे संस्थान हैं जो एक समय पर विदेशों के खिलाफ समाज की ढाल के रूप में सेवा करते थे या उनके पास विदेशियों द्वारा हम पर जोर दिया गया है या हमें उनके द्वारा सरासर अनुकरण में अपनाया गया है। भारतीय संस् कृत के नाम पर ऐसे संःथाओं को संरिक्षत नहीं िकया जा सकता है।

इंटीग्रल मानवतावाद-एकमात्र रास्ता

इंटीग्रल मानवतावाद को आवश्यक रूप से भारतीय और साथ ही पश्चिमी विचारधारा दोनों का संतुलित मूल्यांकन करना चाहिए। इस मूल्यांकन के आधार पर यह एक ऐसा तरीका दिखाने की कोशिश करता है जो मनुष्य को अपनी वर्तमान सोच, अनुभव और उपलब्धि से आगे प्रगति कर सके।

पश्चिमी दुनिया ने बड़ी भौतिक प्रगति हासिल की है, लेकिन आध्यात्मिक प्राप्ति के क्षेत्र में यह बहुत आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है। दूसरी ओर भारत भौतिक उन्नति के पीछे बहुत पीछे है और इसलिए इसकी आध्यात्मिकता एक खोखले-गहरा शब्द बन गई है। नयम अल्मा हहिनेना लखिह (आत्मा को कमज़ोरों के द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है) - भौतिक समृद्धि के बिना कोई आध्यात्मिक उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए यह जरूरी है कि हम ताकत और भौतिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं ताकि हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य का निर्माण कर सकें और दुनिया की प्रगति में योगदान दे सकें, इसके बजाय इस पर बोझ होने की बजाय।

इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नाम है जिसे हमने भारतीय संस्कृति की विभिन्न विशेषताओं, स्थायी, गतिशील, संश्लेषण और उत्कृष्टता के लिए दिया है। यह आदर्श है जो हमारे दिशा निर्धारित करता है। लेकिन हमारे आदर्शवाद में पुरुष कोई भी सिद्धांत नहीं है। प्रथा में एक आदर्श का अनुवाद होना चाहिए इसलिए हमारा कार्यक्रम यथार्थवाद पर आधारित होना चाहिए। दरअसल यथार्थवाद हमारे प्रोग्राम की विशेषता है, हमारी उपलब्धियों का माप और हमारे आदर्श का कसौटी

वर्तमान समय में

केंद्रीय बजट 2017-18 का मुख्य विषय एकीकृत मानवतावाद है। इंटीग्रल मानवतावाद विकेंद्रीकरण पर जोर दिया और हर इंसान की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद महत्व देता है। भारत में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण इस के लिए एक आदर्श उदाहरण है, 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' और 'सबख सथ', 'सबका विकास' (सामूहिक प्रयास, समावेशी विकास) 'प्रत्येक तरह के सिद्धांत हमारी मौजूदा सरकार की नीति, और उसके परिणाम उल्लेखनीय हैं।

कृषि और ग्रामीण विकास 2017-18 के केंद्रीय बजट के मुख्य फोकस क्षेत्रों में से एक है। 157.35 मिलियन हेक्टेयर के साथ, भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कृषि भूमि रखता है। हमारे देश के जीडीपी के लिए कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। कृषि निर्यात देश के निर्यात का 10 प्रतिशत का गठन करता है और यह चौथा सबसे बड़ा निर्याितत प्राचार्य वस्तु है सरकार की पहल और योजनाओं ने इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए कई खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान कर रही है

ई वाणिज्य के लिए इस साल के बजट के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करें

डिजिटल अर्थव्यवस्था

- 125 लाख लोगों ने अब तक बीएचआईएम ऐप को अपनाया है। सरकार बीएचआईएम ऐप के लिए दो नई योजनाएं शुरू करेगी- रेफरल बोनस स्कीम फॉर इंडियाज और कैश-बैक स्कीम के लिए व्यापारियों के लिए आधार आधारबद्ध भुगतान प्रणाली के एक व्यापारी संस्करण का भुगतान, शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा।
- यूपीआई, यूएसएसडी, आधार वेतन, आईएमपीएस और डेबिट कार्ड के माध्यम से 2017-18 के लिए 2,500 करोड़ डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य के साथ एक मिशन की स्थापना की जाएगी।
- एक निर्धारित सीमा से परे, डिजिटल माध्यमों के माध्यम से सभी सरकारी प्राप्तियों को जमानत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

- बैंकों ने मार्च 2017 तक अतिरिक्त 10 लाख नए पीओएस टर्मिनलों को पेश करने का लक्ष्य रखा है। उन्हें सितंबर 2017 तक 20 लाख आधार आधारित पीओएस लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- भारतीय रिज़र्व बैंक में भुगतान विनियामक बोर्ड बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है जो वर्तमान बोर्ड के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण की जगह लेगा।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कदम

- छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए अनुमानित आय की योजना के तहत जिनकी कारोबार 2 करोड़ तक है, वर्तमान में, उनके कारोबार का 8%, जो कि अनुमानित आय के रूप में गिना जाता है, कारोबार के संदर्भ में 6% तक घटा है जो कि गैर-नकद साधनों ।

- कुछ अपवादों के अधीन नकद में 3 लाख रुपये से ऊपर कोई लेन-देन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- एम-पीओएस (मोबाइल फोन या टैबलेट कंप्यूटर के अलावा), माइक्रो एटीएम मानक संस्करण 1.5.1, फिंगर प्रिंट रीडर्स / स्कैनर और आईरिस स्कैनर्स के लिए पीओएस कार्ड रीडर के लिए और ऐसे उपकरणों के निर्माण के लिए उनके मुकाबले और घटकों पर छूट दी गई है बीसीडी, एक्साइज / सीवी शुल्क और एसएडी से

व्यापार करने में आसानी

- घरेलू हस्तांतरण मूल्य का दायरा केवल तब तक सीमित है जब संबंधित पार्टि लेनदेन में शामिल किसी एक संस्था का विनिर्दिष्ट लाभ-निहित कटौती का आनंद होता है।

- व्यवसायिक संस्थाओं की ऑडिट के लिए थ्रेसहोल्ड सीमा, जो प्रणोदक आय स्कीम के लिए चुनते हैं, 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ हो गई। इसी प्रकार, व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए पुस्तकों के रखरखाव के लिए सीमा 10 लाख से 25 लाख तक की कमाई या 1.2 लाख से 2.5 लाख तक की आय में वृद्धि हुई।

- विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (एफपीआई) श्रेणी I और II को अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधान से छूट दी गई है। अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधान भारत के बाहर शेयरों या हितों के मोचन या रिश्वत के मामले में लागू नहीं होगा या भारत में निवेश की बिक्री या बिक्री से उत्पन्न हो सकता है, जो कि भारत में कर के लिए लागू है।

- व्यक्तिगत बीमा एजेंटों को देय आयोग को टीडीएस की आवश्यकता से मुक्त किया जाता है, आत्म-घोषणा करने के लिए कि उनकी आय कम कर योग्य सीमा से कम है

- 50 लाख रुपए तक की रसीद के साथ पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान की योजना के तहत। अग्रिम कर का भुगतान चार के स्थान पर एक किस्त में किया जा सकता है।

- रिटर्न दाखिल करने के लिए समयावधि के साथ, टैक्स रिटर्न में संशोधन करने के लिए समय अवधि वित्तीय वर्ष के पूरा होने से 12 माह तक कम हो रही है। इसके अलावा जांच मूल्यांकन पूरा करने का समय आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 21 महीनों से 18 महीनों तक और आगे और आकलन वर्ष 201 9-20 के लिए और उसके बाद 12 महीनों के लिए संकुचित किया जा रहा है।

संदर्भ

कर्टज, नोरेटा **(2005)**। वैज्ञानिक मूल्य और नागरिक गुण ऑक्सफोर्ड न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस आईएसबीएन **978-0-19-517224- 9**

जॉज़िंग, डेविड (2001) भारत और दक्षिणपूर्व एशिया में धर्म और पारिस्थितिकी लंदन न्यूयॉर्क: रूटलेज आईएसबीएन 0-415-24030-1

टेटरेल्ट, मैरी; डेनमार्क, रॉबर्ट ए (2004) गॉड्स, बंदूकें, और वैश्वीकरण: धार्मिक कट्टरवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था बोल्डर, कोलो: लियन रीनरर पब्लिशर्स। आईएसबीएन 1-58826-253-7

नंदा, मीरा (2003)। पिछड़ा सामना करने वाले भविष्यवक्ताओं: भारत में विज्ञान और हिंदू राष्ट्रवाद के उत्तर-पूर्व आलोचकों न्यू ब्रंसविक, एन.जे .: रटगर्स यूनिवर्सिटी प्रेस आईएसबीएन 0-8135-3357-0

भट्ट, चेतन (2001) हिंदू राष्ट्रवाद, मूल विचारधारा, और आधुनिक मिथकों ऑक्सफोर्ड न्यू यॉर्क: बर्ग आईएसबीएन 1-85 9 73-343-3

मलिक, योगेंद्र (1 99 4) भारत में हिंदू राष्ट्रवादियों: भारतीय जनता पार्टी का उदय बोल्डर: वेस्टव्यू प्रेस आईएसबीएन 0-8133-8810-4

मार्टी, मार्टिन (1 99 3) फंडामेंटलिसम्स और राज्य: रीमकेक पॉलिटिक्स, इकोनॉमीज, और लड़ाकू शिकागो: शिकागो प्रेस विश्वविद्यालय। आईएसबीएन 978-0-226-50884-9

हैंन्सन, थॉमस (1 999)। केसर लहर: आधुनिक भारत में लोकतंत्र और हिंदू राष्ट्रवाद प्रिंसटन, एनजे: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस आईएसबीएन 0-691-00671-7

Corresponding Author

Anita Pandey*

Research Scholar, Mahatama Gandhi Kashi Vidya Peeth University, Varanasi (UP)

E-Mail – anitapandey31@gmail.com